राशन की दुकान से लोगों को छह महीने का अनाज एक साथ उठाने की छूट: पासवान

नई दिल्ली, 18 मार्च (भाषा)।

केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार को कहा कि राशन की दुकानों से सस्ता अनाज पाने के हकदार 75 करोड लोगों को छह माह का राशन एक साथ उठाने की छूट दी जाएगी। अभी उन्हें ज्यादा से ज्यादा दो माह का अनाज समय से पहले उठाने की छट है। केवल पंजाब सरकार है, जिसने लोगों को छह माह का कोटा एक साथ उठाने की अनुमति दे रखी है।

पासवान ने कहा कि हमारे गोदामों में अनाज का पर्याप्त भंडार है। हमने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे गरीब लोगों को छह माह के अनाज का कोटा एक साथ उठाने की छट दें। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच यह निर्णय इसलिए लिया गया है, ताकि आगे किसी प्रकार की पाबंदी के लाग होने पर गरीब लोगों को अनाज पाने में दिक्कत न हो। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी दुकानों से अनाज का उठाव बढने पर सरकारी गोदामों

साबून, थर्मल स्कैनर और डिटॉल की कीमतों पर सरकार की पैनी नजर

नई दिल्ली, 18 मार्च (भाषा)।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस संकट के बीच सरकार अब साबुन, फर्श व हाथ की सफाई वाले क्लीनर और थर्मल स्कैनर जैसी वस्तुओं के दामों पर भी बराबर नजर रखे हुए हैं।

पासवान ने कहा कि हम तीन और वस्तुओं- साबुन, डिटॉल और लाइजॉल जैसे

में जगह का दबाव कम होगा। जगह की कमी के कारण सरकारी खरीद का कुछ गेहूं खुले भंडार केंद्रों पर जमा किया गया है। इस समय सरकारी गोदामों में 4.35 करोड़ टन अधिक अनाज पड़ा हुआ है, जो सुरक्षित बफर स्टाक

फर्श व हाथ साफ करने के तरल क्लीनर के साथ-साथ थर्मल स्कैनर के दामों पर निगाह रखे हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के डर से इनकी मांग बढ़ गई है। इन वस्तुओं के मूल्यों पर देशभर में 114 स्थानों पर नजर रखी जा रही है। सरकार जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत 22 आवश्यक वस्तुओं के मुल्यों की निगरानी करती है। हाल में इसमें चेहरे पर लगाए जाने वाले मास्क और हैंड सेनेटाइजर को भी जोड दिया गया।

की जरूरत से अधिक है। इसमें से 272.19 लाख टन चावल और 162.79 लाख अन गेहं है। पीडीएस के लिए अप्रैल में बफर में 135 लाख टन चावल और 74.2 लाख टन गेहं का भंडार सुरक्षित माना जाता है।

सूचकांक 1,709 अंक गिरा, निफ्टी 8,500 से नीचे आया

मुंबई, 18 मार्च (भाषा)।

शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 29,000 अंक के नीचे आ गया जबिक एनएसई का निफ्टी लगभग 500 अंक नीचे आया।

कोरोना वायरस महामारी का असर जारी

रहने के बीच रेटिंग एजंसी एस एंड पी ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को कम कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर (समायोजित सकल आय) मुद्दे पर दूरसंचार कंपनियों को राहत देने से इनकार कर दिया। इन सबसे बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पडा। बंबई शेयर बाजार का सुचकांक कारोबार के दौरान 2,488.72 अंक का उतार-चढ़ाव आया। अंत में यह 1,709.58 अंक की गिरावट के साथ 28,869.51 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी

498.25 अंक का गोता लगाकर 8,468.80 अंक पर बंद हुआ।

सूचकांक के शेयरों में इंडसइंड बैंक को सर्वाधिक नुकसान हुआ। इसमें 23 फीसद की गिरावट आई। इसके अलावा पावरग्रिड (11.29 फीसद), कोटक बैंक (11.23 फीसद), बजाज फाइनेंस (11.11 फीसद), एचडीएफसी बैंक (9.92 फीसद) और एनटीपीसी (8.08 फीसद) में भी अच्छीखासी गिरावट आई। सूचकांक में केवल ओएनजीसी और आइटीसी के शेयरों में तेजी रही।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजित सकल आय (एजीआर) बकाया के स्व-आकलन को लेकर दुरसंचार कंपनियों की खिंचाई के बाद बैंक और दूरसंचार कंपनियों के शेयर दबाव में रहे। न्यायालय ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को पिछले साल 24 अक्तूबर को दिए गए फैसले में जो राशि तय की गई थी, उसका पूरा भगतान करना होगा।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कोरोना

वायरस महामारी से निपटने के लिए अपने

विकासशील सदस्य देशों के लिए 6.5 अरब डॉलर

महामारी को देखते हुए विकासशील सदस्य देशों की

तात्कालिक मदद के लिए शुरुआती पैकेज की घोषणा

की गई है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय

मनीला में है। बैंक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत

एडीबी ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस

का पैकेज देने की बुधवार को घोषणा की।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार तीन साल के न्यनतम स्तर पर आ गया। निफ्टी 8,500 अंक के नीचे आ गया। यह एशियाई और यूरोपीय बाजारों में गिरावट के अनुरूप है। वैश्विक एजंसियों के कोरोना वायरस माहामारी के कारण वैश्विक मंदी को लेकर चेतावनी दिए जाने के बाद बाजार में गिरावट आई।

भारत में संक्रमण के मामले में बढ़ने और कारोबार बाधित होने से जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को भी कम किया गया है। इससे सरकार के राजकोषीय गणित पर असर पड़ेगा जो पहले से तंग है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दूरसंचार कंपनियों को कोई राहत नहीं मिलने का भी दूरसंचार और बैंक शेयरों पर असर पडा। बैंक शेयरों में गिरावट का कारण दुरसंचार क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिया गया कर्ज हैं।

यह महामारी एक बड़ी वैश्विक समस्या बन गई है।

इसके लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर

साथ हम महामारी से निपटने, गरीबों और अपनी बड़ी

आबादी की सुरक्षा को लेकर आक्रमक कार्रवाई कर रहे

हैं। साथ ही यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था

यथासंभव पटरी पर आए। असाकावा ने कहा कि अपने

सदस्य देशों और समकक्ष संस्थानों से बातचीत के बाद

हम सदस्य देशों की तात्कालिक जरूरतों को परा करने

के लिए 6.5 अरब डॉलर का पैकेज दे रहे हैं। उन्होंने

उन्होंने कहा कि अपने विकासशील सदस्य देशों के

ठोस कदम की जरूरत है।

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

DJ Mediaprint & Logistics Limited

(Formerly known as DJ Logistic Solutions Private Limited)

Our Company was originally incorporated as "DJ Logistic Solutions Private Limited" on February 24, 2009 under the provisions of the Companies Act, 1956 bearing Corporate Identification Number U60232MH2009PTC190567 issued by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. Subsequently name of the company has been changed to "DJ Mediaprint & Logistics Private Limited" vide a Certificate of Incorporation pursuant to change of name dated December 08, 2017. Subsequently our company was converted into Public Limited Company and the name of our Company was changed to "DJ Mediaprint & Logistics Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion from Private Company to Public Company dated December 19, 2017 bearing Corporate Identification Number U60232MH2009PLC190567 issued by the Registrar of Companies, Mumbai. For further details of change in name and registered office of our Company, please refer to section titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no 90 of the Draft Prospectus

Registered office: 24, 1st Floor, Palkhiwala House, Tara Manzil, 1st Dhobi Talao Lane, Mumbai – 400 002, Maharashtra, India. Contact Person: Ms. Khushboo Mahesh Lalji, Company Secretary & Compliance Officer Tel No.: 022 – 2788 9341 E-Mail ID: cs@djcorp.in; Website: www.djcorp.in; CIN: U60232MH2009PLC190567

OUR PROMOTERS: (I) MR. DINESH MUDDU KOTIAN AND (II) MR. SANTHOSH MUDDU KOTIAN

PRICE"), AGGREGATING TO ₹240.00 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 60.000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹20/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹12.00 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 11,40,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹20/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹228.00 LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 28.48% AND 27.05% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

All the investors applying in a public issue shall use only Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility for making payment providing details about the bank accour which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") as per the SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 dated November 10, 2015. As an alternate payment mechanism, Unified Payments Interface (UPI) has been introduced (vide SEBI Circular Ref: SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 as a payment mechanism in a phased manner with ASBA for applications in public issues by retail individual investors. For further details, please refer to section titled "Issue Procedure" beginning on page 173 of the Prospectus. In case of delay, if any in refund, our Company shall pay interest on the application money at the rate of 15 % per annum for the period of delay.

THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIRMENT) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018. (For further details please see "The Issue" beginning on page no. 28 of the Prospectus.) A copy will be delivered for filing to the Registrar of Companies as required under sub-section 4 of Section 26 of the Companies Act, 2013.

For further details please refer the section titled 'Issue Procedure' beginning on page 173 of the Prospectus

FIXED PRICE ISSUE AT 20/- PER EQUITY SHARE

THE APPLICATION MUST BE FOR A MINIMUM OF 6.000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 6.000 EQUITY SHARES THEREAFTER FOR FURTHER DETAILS PLEASE REFER TO "SECTION XI - ISSUE INFORMATION" BEGINNING ON PAGE 166 OF THE PROSPECTUS.

ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPEN ON: 26/03/2020 ISSUE CLOSE ON: 31/03/2020

Mandatory in public issue. No cheque will be accepted

now available in ASBA for retail individual investors.

ASBA is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account For further details check section on ASBA below.'

'ASBA has to be availed by all the Investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and General nformation Documents and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 173

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF THE COMPANY AS REGARDS TO ITS OBJECTS: For information on the main objects of the Company, please see "Our History And Certain Other Corporate Matters" on page 90 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of the

Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, please see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 230 of the Prospectus. AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorised share capital, issued, subscribed and paid up share capital of the Company as on the date of the

Prospectus is as follows: The Authorised Share Capital of the Company is ₹ 1,000 lakhs divided nto 1,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each. The Issued, Subscribed and Paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 301.39 lakhs divided into 30,13,920 Equity Shares of ₹10/- each. Proposed Post issue capital: ₹ 421.39 Lakhs divided into 42,13,920 Equity Shares of ₹10 each. For details of the Capital Structure, see the section "Capital Structure" on the page 40 of the Prospectus. NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association: Equity shares of face value of ₹10/- each were allotted to Dinesh Muddu Kotian- 5000 equity shares and Santhosh Muddu Kotian- 5000 equity shares

LIABILITY OF MEMBERS: Liability of members of Company is Limited RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE: This being the first issue of the issuer, there has been no formal market for the securities of the issuer. The face value of the equity shares is ₹10/- each and the issue price is 2.0 times of face value of the equity share. The issue price should not be taken to be indicative of the market price of the equity shares after the equity shares are listed on the SME

Platform of BSE Limited. No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the equity shares of our company or regarding the price at which the equity shares will be traded after

GENERAL RISKS: Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and vestors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the offer including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document. Specific attention of investors is invited to the statement of 'Risk factors' beginning on page no.18 of the Prospectus.

BASIS FOR ISSUE PRICE: Please refer "Basis for Issue Price" beginning on page 54 of the

ISSUER'S ABSOLUTE RESPONSIBILITY: The issuer, having made all reasonable inquiries, accepts and the issue which is material in the context of the issue, that the information contained in the offer document is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which make this document as a whole or any of such information or the expression of any such opinions or intentions misleading in any material respect

LISTING: The Equity Shares of our company issued through this Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited. In terms of the Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations, as amended from time to time, our company has received "in-principal" approval letter dated ____March, 2020 from BSE for using its name in this offer document for listing of our shares on the SME Platform of BSE Limited. For the purposes of the issue, the Designated Stock Exchange will be BSE Limited

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulation 2018, A copy of the Prospectus has been filed with SEBI after filing of the Offer document with Registrar of Companies in term of Regulation 246 of the SEBI (ICDR) Regulations. 2018 and Sec 26(4) of Companies Act 2013. However, SEBI shall not issue any observation on the Offer document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 157 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE EXHANGE (BSE LIMITED): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to page no. 157 of the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of the BSE.

Ms. Khushboo Mahesh Lalji

Mumbai - 400 002. India

Tel No.: 022 - 2788 9341

E-Mail ID: cs@djcorp.in

Website: www.djcorp.in

DJ Mediaprint & Logistics Limited

1st Dhobi Talao Lane, Marine Lines,

24. 1st Floor, Palkhiwala House, Tara Manzil,

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Investors may contact our Company Secretary and Compliance

Officer and / or the Registrar to the Issue and / or the Lead

Manager, in case of any pre-issue or post-issue related

problems, such as nonreceipt of letters of allotment, credit of

allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or

सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कर सकती है कटौती

एडीबी के अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा ने कहा कि और नीतिगत सलाह देने को तैयार है।

विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए काम करता है। कहा कि एडीबी जरूरत पड़ने पर और वित्तीय मदद

एडीबी ने किया सदस्य देशों के लिए

6.5 अरब डॉलर के पैकेज का एलान

नई दिल्ली, 18 मार्च (भाषा)।

नई दिल्ली, 18 मार्च (भाषा)।

सरकार आगामी तिमाही में छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। ऐसा माना जा रहा है कि इससे रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को घटाने का रास्ता साफ होगा।

सरकार ने मौजूदा तिमाही के दौरान बैंक जमा दरों में कमी के बावजूद सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) जैसी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती नहीं की थी। बैंकरों की शिकायत रही है कि छोटी बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज दर के कारण वे जमा दरों में कटौती नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कर्ज भी सस्ता नहीं हो पाता है। इस समय एक साल की परिपक्वता वाली बैंकों की जमा दर और छोटी बचत दर के बीच

लगभग एक फीसद का अंतर है।

आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ब्याज दर में कटौती के बारे में फैसला करेगी और कोरोना वायरस से उपजी चनौतियों से निपटने के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को तिमाही आधार पर संशोधित किया जाता है। सरकार ने 31 दिसंबर, 2019 को पीपीएफ और एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को चाल वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 7.9 फीसद पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया था, जबकि 113 महीनों की परिपक्व वाले किसान विकास पत्र की दर 7.6 फीसद रखी गई थी। सरकार ने कहा था कि जनवरी-मार्च 2020 तिमाही के दौरान सुकन्या समृद्धि योजना 8.4 फीसद की दर से प्रतिफल देंगी।

अब एसएंडपी ने घटाया भारत की विकास दर का अनुमान

नई दिल्ली, 18 मार्च (भाषा)।

एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स ने 2020 में भारत की वैश्विक आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाकर 5.2 फीसद कर दिया है और कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में प्रवेश कर रही है।

इससे पहले एजंसी ने 2020 में भारत में 5.7 फीसद की दर से विकास होने का अनुमान जताया था। एस एंड पी ने एक बयान में कहा कि दुनिया मंदी

के दौर में प्रवेश कर रही है। एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स में एशिया-प्रशांत के लिए प्रमुख अर्थशास्त्री शॉन रोशे ने कहा कि चीन में पहली तिमाही में बड़ा झटका, अमेरिका और यूरोप में शटडाउन और स्थानीय विषाण संक्रमण के कारण एशिया-प्रशांत में बड़ी मंदी पैदा होगी। एस एंड पी ने कहा कि हम चीन, भारत और जापान में 2020 में होने वाले विकास के अनुमान को कम कर क्रम से (पहले के 4.8 फीसद, 5.7 फीसद और 0.4 फीसद) 2.9 फीसद, 5.2 फीसद और 1.2 फीसद कर रहे हैं।

येस बैंक का शेयर चार दिनों में 251 फीसद बढ गया

नई दिल्ली, 18 मार्च (भाषा)।

येस बैंक के शेयरों में बुधवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र के दौरान तेजी रही। एसबीआइ ने कहा कि वह बैंक में 49 फीसद तक हिस्सेदारी हासिल करने का इच्छुक है, जिसके बाद उसके शेयरों में 50 फीसद का उछाल देखने को मिला।

49.95 फीसद बढ़कर 87.95 रुपए पर पहुंच गए। एनएसई में येस बैंक के शेयर 48.84 फीसद बढ़कर 87.30 रुपए के भाव पर थे। इस तरह चार दिनों में शेयर 251 फीसद बढ़ गया है। इससे पहले मूडीज ने मंगलवार को येस बैंक की रेटिंग को अपग्रेड किया था, जिसके बाद उसके शेयरों में 59 फीसद की छलांग देखने को मिली। बैंक की पनर्गठन योजना की घोषणा के बाद से उसके शेयरों में लगातार तेजी है।

एसबीआइ के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा कि येस बैंक में एसबीआइ की हिस्सेदारी करीब 43 फीसद शुरुआती कारोबार के दौरान येस बैंक के शेयर है और अब तीन साल की लॉक-इन अवधि से पहले उनका बैंक येस बैंक के एक भी शेयर नहीं बेचेगा। उन्होंने कहा कि वह बोर्ड से येस बैंक में हिस्सेदारी बढाकर 49 फीसद करने के लिए बात करेंगे।

सरकार की देनदारी दिसंबर के अंत में बढ़कर 93.89 लाख करोड़ पहुंची

नई दिल्ली, 18 मार्च (भाषा)।

सरकार पर कुल देनदारी दिसंबर 2019 के अंत में इससे पूर्व तिमाही के मुकाबले 3.2 फीसद बढ़कर 93.89 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई।

वित्त मंत्रालय के बुधवार को जारी आंकड़े के अनुसार सितंबर 2019 में लोक खाते के अंतर्गत देनदारी समेत कुल 91,01,484 करोड़ रुपए थी। दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में कुल बकाया देनदारी का 90.4 फीसद सार्वजनिक ऋणों के मद का था। लोक ऋण प्रबंधन तिमाही रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2019 के अंत तक एक साल से कम अवधि में परिपक्व होने वाले बांड (कर्ज) का अनुपात बढ़

कर कुल देनदारी के 6.64 फीसद के बराबर पहुंच गया था। इससे पूर्व तिमाही में अल्पकालिक कर्ज का अनुपात 5.41 फीसद था।

इसी तरह एक-पांच साल के अंदर की परिपक्वता अवधि के बांड का अनपात आलोच्य तिमाही के अंत में 25.09 फीसद रहा, जो सितंबर 2019 को समाप्त तिमाही में यह 23.65 फीसद था। रिपोर्ट के अनुसार इसी समय अगले पांच साल में परिपक्व होने वाले कर्ज का अनुपात 31.7 फीसद था। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के प्रतिफल (ईल्ड) में अक्तूबर-नवंबर 2019 के दौरान घट-बंढ सीमित दायरे में रही। दिसंबर को पहले पखवाड़े में इसमें कुछ तेजी आई।

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

FINSHORE

FINSHORE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Anandlok", Block-A, 2nd Floor, Room No. 207, 227 A.J.C Bose Road, Kolkata-700020, West Bengal Telephone: 033 – 22895101

Email: ramakrishna@finshoregroup.com **Website:** www.finshoregroup.com Investor Grievance Email: info@finshoregroup.com Contact Person: Mr. S. Ramakrishna Iyengar

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Opp. Kasturba Hospital Lane, Lower Parel (E) Mumbai – 400011. Maharashtra

REGISTRAR TO THE ISSUE

Tel: 022 2301 2518 / 8261, Email/ Investor Grievance E-mail support@purvashare.com Contact Person: Ms. Deepali Dhuri - Compliance Officer

SEBI Registration No: INR000001112 **CIN No:** U67120MH1993PTC074079

SEBI Registration No: INM000012185 CIN No: U74900WB2011PLC169377

refund orders, etc. Availability of Prospectus: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk

Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com, the website of Lead Manager at www.finshoregroup.com and website of Issuer Company at www.djcorp.in. Availability of Application form: Application forms can be obtained from the Registered Office of DJ Mediaprint & Logistics Limited and the Lead Manager to the Issue

Finshore Management Services Limited. Application Forms will be available at the selected location of registered brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can be obtained from the website of Stock Exchange and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of BSE & SEBI. Applications Supported by Blocked Amount (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed by all the investors. The investors

are required to fill the application from and submit the same to the relevant SCSB's at the specific locations or registered brokers at the broker centres or RTA or DP's. The SCSB's will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. The ASBA application forms can also be downloaded from the website of BSE. ASBA application forms can be obtained from the Designated Branches of SCSB's, the list of banks that are available on website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia. com. For more details on ASBA process, please refer to the details given in application forms and Prospectus and also please refer to the Section "Issue Procedure" beginning on page173 of the Prospectus.

UNIFIED PAYMENTS INTERFACE (UPI): Investors are advised to carefully refer SEBI circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018 and SEBI Circular No SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 for details relating to use of Unified Payments Interface (UPI) as a payment mechanism with Application Supported by Block Amount (ASBA) for applications in public issues by retail individual investors.

BANKER TO THE ISSUE\SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

Investor should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors beginning on page 18 of the Prospectus before making any investment decision.

For DJ Mediaprint & Logistics Limited On behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai Date: 18/03/2020

Managing Director DJ Mediaprint & Logistics Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, a public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the

Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.finshoregroup. com, website of the BSE at www.bseindia.com and website of Issuer Company at www.djcorp.in. Investor Should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus, including the section titled "Risk Factors" as appearing in the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities laws in United States and will not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of U.S. persons" (as defined in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933.

www.readwhere.com